

Vol 6 Issue 1 Feb 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pintea, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences AL. I. Cuza University, Iasi	More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yalikal Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal

International Recognized Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 2230-7850

Impact Factor : 4.1625 (UIF)

Volume - 6 | Issue - 1 | Feb



कृषि एवं खाद्य सुरक्षा



उमेश कुमार शाक्य

असि. प्रोफे. (अर्थशास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, जलालाबाद (शाहजहाँपुर).

प्रस्तावना –

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यन्त महत्वपूर्ण सीन है इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। देश की कृषि, पूरी श्रम शक्ति के लगभग 52 प्रतिशत को रोजगार प्रदान करती है। देश के नियोजित विकास और औद्योगीकरण के पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 1950–51 के 56.44 प्रतिशत से घटा अवश्य है परन्तु अभी भी (2011–12 में) सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 13.9 प्रतिशत है। जहाँ एक ओर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का घटता हुआ प्रतिशत इस बात को दर्शाता है कि देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और कृषि पर निर्भरता घट रही है वहीं दूसरी ओर चिन्ताजनक पहलू यह है कि देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और यह 1950–51 में 36.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.01 करोड़ पर पहुँच गयी है जो कि सम्पूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है जबकि भू-क्षेत्रफल पूरे विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में भूख एवं कुपोषण से सुरक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08 के अनुसार 1990 से वर्ष 2007 तक खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत रही है जबकि इसी दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रही है। इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम रही है। बढ़ती हुयी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने, आर्थिक दर और विकास की खातिर बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि के कारण कृषि जोत का क्षेत्रफल घट रहा है। वर्ष 1971 में जोत का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर था जो वर्ष 1990–91 में घटकर 1.57 हेक्टेयर हो गया। वर्ष 1950–51 में जहाँ 76 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसल की जाती थी वह वर्ष 2003–04 में घटकर 65.6 प्रतिशत रह गयी। हरित क्रान्ति की सफलता, 1993 की पोषण नीति, 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना एवं 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आदि प्रयासों के बावजूद यह हकीकत ही है कि आज भी भूख और कुपोषण से निजात नहीं मिल पायी है यद्यपि देश ने कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की है लेकिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं। वर्ष 1950–51 में खाद्यान्न उत्पादन 5.082 करोड़ टन था जो 2011–12 में बढ़कर 24.478 करोड़ टन हो गया जबकि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता वर्ष 1950–51 में 394.9 ग्राम 1991 में 510.10 ग्राम तथा 2011 में घटकर 438.6 ग्राम हो गयी।



भारत में जनसंख्या, खाद्यान्न उत्पादन एवं उपलब्धता (ग्राम में)

वर्ष	जनसंख्या (लाख)	खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	उपलब्धता (किलोग्राम प्रति व्यक्ति)
1951	36.1	50.82	394.9
1961	43.9	82.02	468.7
1971	54.8	108.42	468.8
1981	68.3	129.59	454.8
1991	84.6	176.39	510.1
2001	102.0	196.81	416.2
2011	121.01	244.78	438.6

स्रोत— आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि सहकारिता विभाग

गरीबी, कुपोषण, रोजगार तथा भूख का एक—दूसरे से गहरा संबंध होता है। वर्ष 2008 में इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाये गये 80 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 66वाँ स्थान था। यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार भारत में 20 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं जबकि 30 प्रतिशत शिशु औसत से कम बजन के पैदा होते हैं। 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 15 से 49 वर्ष की 57.8 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत की एक तिहाई आबादी (32.7 प्रतिशत) अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है जबकि भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत हालिया आकड़ों के अनुसार देश में गरीबी की दर तेजी से घटी है। योजना आयोग के अनुसार 2011—12 में देश की 21.9 प्रतिशत जनसंख्या ही गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है।

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्मन सेन का कहना है कि गरीबी और भुखमरी को जोड़कर देखा जाना चाहिए। संकट यह नहीं है कि देश में अनाज का संकट है या उत्पादन अचानक न्यूनतम स्तर पर आ गया है। असली संकट यह है कि लोगों के पास अनाज को खरीदने की क्रयशक्ति नहीं है। गरीबी के कारण भुखमरी और कुपोषण को बढ़ावा मिलता है जिससे शारीरिक और मानसिक शक्तिहीनता बढ़ती है और इसके फलस्वरूप श्रम की उत्पादन क्षमता तथा सकल मात्रा घटती है। यह स्थिति उत्पादन को घटाती है और कम उत्पादन गरीबी को बढ़ा देता है। इस प्रकार गरीबी और भुखमरी का दुश्चक्र आरम्भ हो जाता है।

करोड़ों लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता देश के किसानों पर निर्भर है लेकिन गाँवों में गरीबी फैली हुई है। अतः जब खेती करने वाले किसानों और ग्रामीणों को भरपेट भोजन उपलब्ध न हो तो वे खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने में भूमिका नहीं निभा सकते। गरीबी के साथ ही जलवायु में परिवर्तन के कारण भी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सितम्बर 2009 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार औसत तापमान में प्रति डिग्री बढ़त से भारत में गेहूँ की उपज में प्रतिवर्ष 60 लाख टन की कमी हो जायेगी। इसी तरह से अन्य फसलों पर भी प्रभाव सम्भव है। इससे वैश्विक उत्पादन में आने वाली कमी का भी सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है।

विश्व खाद्य संगठन के हाल के प्रतिवेदन के अनुसार देश में हर साल 50 हजार करोड़ रुपये का भोजन बर्बाद हो जाता है जो देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत हैं। 12 सितम्बर 2013 को जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुचित गतिविधियों के कारण पैदा किये जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा अर्थात करीब 1.3 अरब टन खाद्यान्न बर्बाद कर दिया जाता है जबकि विश्व के 87 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे रहने को विवश हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में समुचित भण्डारण के अभाव में एफ0सी0आई0 की गोदामों में लगभग 30 प्रतिशत अनाज सड़ जाता है।

गरीब वर्ग क्रय शक्ति के अभाव में खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होता है और इस कारण से खाद्यान्नों की उपलब्धता होने पर भी उसके लिए खाद्यान्न हासिल कर पाना सम्भव नहीं होता इसलिए गरीबी, कुपोषण और खाद्य की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी है जिससे भारत भोजन का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। इसके तहत देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभ होगा। इस योजना में गरीबों को रू0 2 प्रति किग्रा0 गेहूँ, रू0 3 प्रति किग्रा0 चावल तथा रू0 1 प्रति किग्रा0 की दर से मोटा अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस योजना के लिए 6.12 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता बतायी गयी है जिससे सरकार पर 1 लाख 24 हजार 724 करोड़ रू0 का सब्सिडी का भार आने आंकलन किया गया है। योजना में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गयी है तथा 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए उनके विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की भी व्यवस्था है। सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली इस प्रकार की योजनाओं के कारण खाद्य सब्सिडी की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है। जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है—

सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी की मात्रा

वर्ष	सब्सिडी (करोड़ रुपये)
2007&08	31259-68
2008&09	43668-08
2009&10	58242-45
2010&11	65929-56
2011&12	85000-00
2012&13	90000-00

स्रोत— खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य सब्सिडी वर्ष 2007–08 के 31259.08 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 90000.00 करोड़ रुपये पर पहुँच चुकी है।

कृषि में घटते निवेश और मौसम की अनिश्चतता के कारण कृषि की विकास दर मंद पड़ गयी है। जनगणना के आकड़ों के मुताबिक 1991 से 2001 के बीच 80 लाख लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। देश की कृषि का लगभग 60 प्रतिशत भाग आज भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। विकास के लिए आवश्यक सड़के, हवाई अड्डे, औद्योगिक कारखाने, महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के लिए इमारतें बनाने आदि के लिए उर्वरक जमीन को ही उपयो में लाया जा रहा है जबकि देश के कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 70 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि (कुल भूमि का 26 प्रतिशत) कृषि योग्य बनाने लायक समतल भूमि है जिसे खेती योग्य बनाने के लिए समुचित, ठोस एवं कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

बंजर भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रभावी बनाकर कृषि क्षेत्र बढ़ाना होगा। औद्योगिक इकाइयों को लगाने, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने आदि के लिए बेकार व परती पड़ी भूमि के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। कृषि योग्य जमीन को अन्य प्रयोगों में लाने से बचना होगा। खाद्यान्नों के भण्डारण की क्षमता बढ़ानी होगी तथा अनाज के अपव्यय को रोकना होगा। अधिक उपज देने वाली किस्सों में सुधार एवं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत कृषि पर समझौता के अनुसार, प्रत्येक देश अपने कुल उत्पाद मूल्य के 10 प्रतिशत तक ही सब्सिडी दे सकता है जबकि खाद्य सब्सिडी की तेजी से बढ़ती मात्रा एवं देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाने के प्चात भारत की खाद्य सब्सिडी 10 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन के दण्ड से बचने के लिए विश्व व्यापार संगठनों के नियमों में परिवर्तन करके सब्सिडी की सीमा बढ़ाने के लिए भारत को विश्व व्यापार संगठन पर दबाव बनाना होगा तथा दीर्घकाल में खाद्य सब्सिडी की मात्रा को सीमित रखने के लिए, उत्पादन वृद्धि के सभी सम्भव एवं कारगर उपाय अपनाने के साथ—साथ जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण रखना होगा। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून निश्चित ही एक बड़ा कदम है लेकिन खाद्य सुरक्षा के गम्भीर मामले को केवल इस कानून के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भूख तथा कुपोषण की समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए गरीबी हटा कर क्रयशक्ति बढ़ाने एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो कि कृषि के विकास के बिना सम्भव नहीं है।

साभार संदर्भ—

1. दैनिक, राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप), लखनऊ, 08 मई 2010 (पृ. सं. 1–4)
2. वही, 5 फरवरी 2011 (पृ. सं. 1–4)
3. दैनिक, राष्ट्रीय सहारा लखनऊ, 02 जनवरी 2015 (पृ. सं. 10)
4. दैनिक जागरण, कानपुर, 21 सितम्बर 2010 (पृ. सं. 10)
5. दैनिक कल्पतरु एक्सप्रेस, मथुरा, 15 दिसम्बर 2013 (पृ. सं. 10)
6. दैनिक अमर उजाला, बरेली, 28 जुलाई 2010 (पृ. सं. 10)
7. राकेश रोशन एवं नवीन कुमार, भारतीय अर्थव्यवस्था, अरिहन्त प्रकाशन मेरठ
8. प्रतियोगिता दर्पण (मासिक) आगरा, जनवरी 2014
9. वही, नवम्बर 2014
10. योजना (मासिक), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2010
11. वही, अक्टूबर 2010
12. वही, जनवरी 2011

13. वही, दिसम्बर 2013
14. कुरुक्षेत्र (मासिक), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, दिसम्बर 2013
15. वही, अक्टूबर 2014



me'k dekj 'kkD;
vfl- ikQ- %vFk'kkL=%j jkt dh; egkfo|ky;
t ykykcn %'kkgtgkij%

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org